RNI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 253
दि. 13.01.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

संसद की गरिमा बनाम व्यक्तिगत आचरण: ई-सिगरेट प्रकरण में कीर्ति आज़ाद की सांसदी पर संकट गहराया

(जीएनएस)। नई दिल्ली। संसद भवन परिसर के भीतर ई-सिगरेट के कथित उपयोग से जुड़ा मामला अब केवल एक अनुशासनहीनता का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह संसदीय मर्यादा, संवैधानिक मूल्यों और जनप्रतिनिधियों के आचरण से जुड़ी व्यापक बहस का विषय बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद के खिलाफ लगे आरोपों के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी गंभीर संकट के संकेत सामने आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की हालिया टिप्पणी ने इस पूरे प्रकरण को और संवेदनशील बना दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत निष्कासन तक की कार्रवाई संभव है और संसद की गरिमा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।

संसद भवन को देश की लोकतांत्रिक आस्था का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। यहां न केवल कानून बनते हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के आचरण से लोकतंत्र की नैतिक शक्ति भी झलकती है। ऐसे में संसद के भीतर किसी प्रतिबंधित वस्तु के उपयोग का आरोप अपने आप में गंभीर माना जाता है। ई-सिगरेट के उपयोग को लेकर संसद परिसर में पहले से ही सख्त नियम लागू हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुशासन दोनों ही दृष्टि से इसे अनुचित माना गया है। यही कारण है कि कीर्ति आज़ाद से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है।

सोमवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक सांसद की सामूहिक जिम्मेदारी है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को छूट नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष ने संकेत दिए कि कीर्ति आज़ाद से जुड़े मामले की प्रारंभिक जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसे संबंधित संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि

अध्यक्ष स्वयं अंतिम फैसला नहीं लेते, बल्कि यह सदन का विशेषाधिकार होता है कि वह नियमों के तहत क्या कार्रवाई उचित समझता है।

लोकसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसद के नियमों में सदस्यता समाप्त करने का भी प्रावधान मौजूद है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व में संसदीय आचरण के उल्लंघन के मामलों में सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब संसद में आचरण, अनुशासन और सार्वजनिक मर्यादा को लेकर पहले से ही बहस चल रही है। ऐसे में यह मामला एक मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका असर भविष्य में अन्य मामलों पर भी पड़ सकता है।

इस पूरे प्रकरण की जड़ शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आई शिकायत से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कीर्ति आज़ाद को संसद भवन के भीतर ई-सिगरेट का उपयोग करते हुए देखा गया। अनुराग ठाकुर का दावा है कि यह दृश्य केवल उन्होंने ही नहीं, बल्कि कई अन्य सांसदों ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस कृत्य को उन्होंने संसदीय मानद आचरण का गंभीर उल्लंघन बताया और मामले की जांच की मांग की। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही यह मामला राजनीतिक और संसदीय गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष इसे संसद की मर्यादा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक इस मामले में कोई आक्रामक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के भीतर भी इसे लेकर असहजता देखी जा रही है।

कीर्ति आज़ाद स्वयं एक अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे में उनके खिलाफ लगे आरोपों ने राजनीतिक दृष्टि से भी इस मामले को संवेदनशील बना दिया है।

कानूनी और संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल ई-सिगरेट के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सांसदों के आचरण और संसद के भीतर अनुशासन की व्यापक परिभाषा से जुड़ा है। संसद के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सदन और उसके परिसर में किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण, जो गरिमा को ठेस पहुंचाए, अस्वीकार्य है। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं, तो चेतावनी, निलंबन या यहां तक कि सदस्यता समाप्त करने जैसे विकल्प भी खुले रहते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राजनीतिक सहमति और सदन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनप्रतिनिधि अपने आचरण में वही अनुशासन दिखाते हैं, जिसकी अपेक्षा वे आम नागरिकों से करते हैं। संसद के भीतर नियमों का उल्लंघन केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाती, बल्कि इससे पूरे सदन की छवि प्रभावित होती है। यही कारण है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इसे व्यक्तिगत मामला न मानते हुए संस्थागत गरिमा से जोड़कर देखा है।

अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और उससे जुड़ी समिति की सिफारिशों पर टिकी हैं। जैसे ही यह रिपोर्ट सदन के सामने आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह तय है कि इस प्रकरण का असर केवल कीर्ति आज़ाद की राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संसद में अनुशासन और आचरण से जुड़े मानकों को भी नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर लगातार चर्चा हो रही है, यह मामला संसद के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें यह तय होगा कि नियमों और मर्यादा के सवाल पर सदन कितना कठोर और निष्पक्ष रुख अपनाता है।

आरक्षण की परिधि पर नई बहस: एससी-एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दखल

(जीएनएस)। दिल्ली। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू करने की मांग को लेकर एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे खटखटाए गए हैं और इस बार यह मुद्दा गंभीर संवैधानिक बहस के केंद्र में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील विषय पर सभी पक्षों की राय और संवैधानिक पहलुओं को सुनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि जिस तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हो चुके वर्गों की पहचान की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी से जूझ रहे लोगों को मुख्यधारा में लाना है, न कि उन परिवारों को बार-बार लाभ पहुंचाना जो पहले ही इस व्यवस्था के माध्यम से ऊंचा सामाजिक और आर्थिक दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। याचिका में यह भी तर्क रखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार ने एक बार आरक्षण का लाभ लेकर स्थायी सामाजिक उन्नति हासिल कर ली है, तो उसकी अगली पीढ़ी को उसी लाभ का स्वतः अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होने से आरक्षण का वास्तविक लाभ सीमित हाथों में सिमट जाता है और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोग इससे वंचित रह जाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि एससी-एसटी समुदाय के भीतर भी एक ऐसा वर्ग उभर आया है, जो प्रशासनिक सेवाओं, उच्च शिक्षा और आर्थिक संसाधनों में मजबूत स्थिति में है, जबकि उसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आज भी बुनियादी सुविधाओं और अवसरों से वंचित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाना इस मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यह विषय लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है, लेकिन अब यह सीधे संवैधानिक व्याख्या के दायरे में प्रवेश कर गया है। अब अदालत को यह तय करना होगा कि क्या संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था में समानता के सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्रीमी लेयर जैसी अवधारणा को एससी-एसटी आरक्षण में भी लागू किया जा सकता है, या फिर यह व्यवस्था इन समुदायों के लिए एक अलग ऐतिहासिक संदर्भ में तय की गई है, जिसमें आर्थिक समृद्धि के बावजूद सामाजिक भेदभाव की निरंतरता को प्राथमिक आधार माना गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई थी कि आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों तक पहुंचे, जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। सामान्यतः क्रीमी लेयर में वे परिवार या व्यक्ति माने जाते हैं, जिनकी आय एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, या जिनके माता-पिता उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हों, अथवा जिन्होंने पहले ही आरक्षण के माध्यम से स्थायी उन्नति प्राप्त कर ली हो। ओबीसी वर्ग में इस सिद्धांत के लागू होने के बाद यह देखा गया कि आरक्षण के लाभ का अधिक समान वितरण संभव हो पाया, हालांकि इस पर भी समय-समय पर विवाद होते रहे हैं।

कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गहरी साजिश बेनकाब, बंगाल से तीन शूटर दबोचे गए

(जीएनएस)। कोलकाता। पंजाब के चर्चित कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से तीन ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका सीधा संबंध कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक नेटवर्क से बताया जा रहा है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक हाई-प्रोफाइल हत्या की गुत्थी सुलझाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है, बल्कि यह भी उजागर किया है कि कैसे संगठित अपराधी गिरोह अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का सहारा लेकर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हावड़ा के गोलाबाड़ी थाना क्षेत्र में की गई सुनियोजित छापेमारी के दौरान पंजाब निवासी करण पाठक, तरणदीप सिंह और आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि ये तीनों आरोपी राणा बालाचौरिया की हत्या के बाद तुरंत पंजाब से

फरार हो गए थे। खुद को पुलिस की पकड़ से दूर रखने के लिए उन्होंने पहले नेपाल की सीमा पार की और वहां से सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे, जहां कुछ समय तक छिपकर रहने के बाद वे दोबारा भारत लौट आए।

जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। भारत लौटने के बाद उन्होंने कोलकाता और आसपास के इलाकों को अस्थायी शरणस्थली के रूप में चुना। पुलिस को इनपुट मिला था कि वे पश्चिम बंगाल से किसी अन्य राज्य में जाने की फिराक में हैं और हावड़ा स्टेशन के जरिए ट्रेन से फरार होने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें धर दबोचा। गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2025 को पंजाब में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान राणा बालाचौरिया की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के बेहद करीब पहुंचे और अचानक गोलियां चला दीं। इस वारदात ने खेल जगत के साथ-साथ पूरे पंजाब में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जिम्मेदारी लेने के संकेत भी सामने आए थे, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि मामला संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस शुरू से ही इस हत्याकांड को गैंगवार और संगठित अपराध के नजरिए से देख रही थी। लगातार छापेमारी, तकनीकी सर्विलांस और अंतरराज्यीय समन्वय के बाद आखिरकार आरोपियों की लोकेशन पश्चिम बंगाल में ट्रेस की गई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के शूटर अक्सर वारदात के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में फैल जाते हैं और कभी-कभी नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी शरण लेते हैं, जहां से उन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि हत्या की साजिश, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और गैंग के अन्य सदस्यों की भूमिका को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आएंगी। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें पेशेवर तरीके से काम सौंपा गया था और इसके लिए उन्हें अलग-अलग चैनलों के जरिए निर्देश मिल रहे थे।

एआई के वैश्विक मानचित्र पर भारत की निर्णायक छलांग, उत्तर प्रदेश बनेगा नवाचार की नई प्रयोगशाला

(जीएनएस)। लखनऊ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने जिस तेजी से प्रगति की है, वह अब दुनिया के लिए एक उदाहरण बनती जा रही है। केंद्रीय आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने सोमवार को कहा कि एआई को अपनाने और उसके व्यावहारिक उपयोग के मामले में भारत आज विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने यह बात उत्तर प्रदेश एआई एवं स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इस मंच से यह संकेत भी दिया गया कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े एआई इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है। जितिन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक को केवल शहरी और कॉरपोरेट दायरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम नागरिक के जीवन से जोड़ने का ठोस प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि एआई के क्षेत्र में भारत की बढ़त केवल प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, शिक्षा और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी साफ दिखाई दे रही है। मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने मिलकर भारत को एआई आधारित समाधानों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एआई का वास्तविक लाभ तब माना जाएगा, जब इसका असर गांवों और दूरदराज के इलाकों में दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एआई आधारित पूर्वानुमान प्रणाली से किसानों को मौसम, फसल रोग और बाजार मूल्य की सटीक जानकारी मिल सकती है, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का उपयोग शुरुआती जांच, रोगों की पहचान और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ सेवाएं पहुंचाने में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जिससे सीखने की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य सरकार एआई और उभरती तकनीकों को विकास का अहम औजार मानती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क, डेटा सेंटर और तकनीकी विश्वविद्यालयों के जरिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो नवाचार को बढ़ावा दे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में कई पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें एआई आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स शामिल हैं।

इस सम्मेलन में देश-विदेश से आए तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने एआई के भविष्य और उसके सामाजिक प्रभावों पर अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत की बड़ी जनसंख्या और विविध जरूरतें एआई के लिए एक बड़ी चुनौती होने के साथ-साथ अवसर भी हैं।

यात्री की तबीयत बिगड़ते ही बदला गया उड़ान मार्ग, जयपुर में सुरक्षित उतरी एयर इंडिया की फ्लाइट

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली से विजयवाड़ा जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान सोमवार सुबह उस समय अचानक सुर्खियों में आ गई, जब विमान में सवार एक बुजुर्ग यात्री की तबीयत उड़ान के दौरान गंभीर रूप से बिगड़ गई। इस अप्रत्याशित स्थिति में पायलट और केबिन क्रू ने त्वरित निर्णय लेते हुए विमान को जयपुर की ओर मोड़ दिया और वहां सुरक्षित आपात लैंडिंग कराई गई। इस फैसले से न सिर्फ यात्री की जान बचाने में मदद मिली, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि संकट की घड़ी में मानवीय संवेदनाएं और पेशेवर जिम्मेदारी किस तरह साथ-साथ निभाई जाती हैं। जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-2517 सोमवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विजयवाड़ा के लिए रवाना हुई थी। उड़ान सामान्य रूप से अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी, तभी कुछ समय बाद केबिन में एक बुजुर्ग यात्री को अचानक बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। यात्री की हालत बिगड़ती देख उनके साथ सफर कर रहे परिजनों ने तुरंत केबिन क्रू को इसकी सूचना दी। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स ने मानक प्रक्रियाओं के तहत प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता देना शुरू किया और स्थिति की गंभीरता का आकलन किया।

जैसे-जैसे यात्री की हालत स्थिर होने के बजाय और चिंताजनक होती गई, केबिन क्रू ने पायलट को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर हालात से अवगत कराया और निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति मांगी। चिकित्सा आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए विमान को जयपुर हवाई अड्डे की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया, ताकि लैंडिंग के तुरंत बाद आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

विमान के जयपुर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस को तैनात कर दिया गया था। जैसे ही विमान ने सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड किया, मेडिकल स्टाफ तुरंत विमान के भीतर पहुंचा और यात्री की जांच की। प्राथमिक आकलन के बाद बुजुर्ग यात्री को एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर अस्पताल पहुंचने से स्थिति को संभालने में काफी मदद मिली और यात्री की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

इस आपात स्थिति के दौरान विमान में सवार अन्य यात्रियों को कुछ समय तक असमंजस और चिंता का सामना करना पड़ा, लेकिन क्रू मेंबर्स ने संयम और स्पष्ट संवाद के जरिए यात्रियों को स्थिति की जानकारी दी और उन्हें शांत रखा। यात्रियों ने भी धैर्य और सहयोग का परिचय दिया। कई यात्रियों ने बाद में कहा कि भले ही उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए लिया गया यह फैसला पूरी तरह उचित और सराहनीय था।

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और किसी भी आपात स्थिति में मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत निर्णय लिया जाता है। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि जयपुर में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और स्थिति की समीक्षा के बाद आगे की उड़ान को लेकर फैसला किया जाएगा।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

ईरान की सड़कों पर उबलता आक्रोश और सत्ता की कठोर परीक्षा

ईरान एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां सड़कों पर उठता जनाक्रोश केवल किसी एक घटना या तात्कालिक असंतोष का परिणाम नहीं दिखता, बल्कि यह दशकों से जमा होते असंतुलन, दमन और अवरुद्ध आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति बन चुका है। कट्टरपंथी धार्मिक शासन के खिलाफ समय-समय पर विरोध के स्वर ईरान में पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन मौजूदा आंदोलन अपनी तीव्रता, व्यापकता और सामाजिक संरचना के लिहाज से पिछले एक दशक में सबसे गंभीर माना जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों को 'ईश्वर का शत्रु' करार देना, मृत्युदंड की धमकियां देना और सख्त दमनकारी कार्रवाइयां करना यह संकेत देता है कि सत्ता संवाद के बजाय शक्ति के सहारे स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब जनभावनाओं को लंबे समय तक दबाया जाता है, तो वह आक्रोश अंततः और अधिक विस्फोटक रूप में सामने आता है। ईरान का मौजूदा संकट दरअसल एक ऐसे समाज और सत्ता के बीच टकराव का प्रतीक है, जिनकी दिशाएं एक-दूसरे से लगातार दूर होती जा रही हैं। एक ओर एकीकृत, कठोर और धर्म आधारित सत्ता संरचना है, जो जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर एक युवा, शिक्षित और वैश्विक प्रभावों से जुड़ा समाज है, जो अधिक खुलेपन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहा है। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जिसने इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक संपर्कों के जरिए दुनिया के अन्य देशों में सामाजिक बदलाव, आर्थिक प्रगति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उदाहरण देखे हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि वे अपने देश में भी उसी तरह की संभावनाओं और अवसरों की उम्मीद करें। सत्ता और युवाओं के बीच यह बढ़ती खाई केवल सांस्कृतिक या वैचारिक नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध आर्थिक संकट से भी है। ईरान पर वर्षों से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, विशेष रूप से उसकी परमाणु नीति के कारण लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा अवमूल्यन और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की जिंदगी को कठिन बना दिया है। जब आर्थिक दबाव और सामाजिक नियंत्रण एक साथ बढ़ते हैं, तो असंतोष का विस्फोट होना लगभग तय हो जाता है। मौजूदा प्रदर्शन उसी हताशा और गुस्से का परिणाम हैं, जो लंबे समय से भीतर सुलग रहा था। शासन की ओर से दमन को समाधान के रूप में चुनना अल्पकालिक तौर पर सड़कों को शांत कर सकता है, लेकिन इससे सत्ता की वैधता पर सवाल और गहरे होते जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों से दूर किसी भी शासन के लिए जनता की स्वीकृति सबसे बड़ा आधार होती है। जब संवाद की जगह भय, सजा और हिंसा ले लेती है, तो शासन और जनता के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी हो जाती है। ईरान में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। सत्ता की कठोर प्रतिक्रिया से यह संदेश जाता है कि सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसे कुचलने पर आमादा है। यह रवैया लंबे समय में स्थिरता के बजाय और अधिक अस्थिरता को जन्म देता है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी ईरान की स्थिति जटिल बनी हुई है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ उसके संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए पश्चिमी देश ईरान की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन अक्सर यह आलोचना भू-राजनीतिक हितों से प्रेरित दिखती है। प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबावों ने ईरान की सरकार को कमजोर करने के बजाय आम जनता की जिंदगी को अधिक कष्टदायक बनाया है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि आर्थिक प्रतिबंधों से सत्ता संरचना शायद ही कभी टूटती है, लेकिन उनकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। ईरान में भी यही हुआ है, जहां महंगाई और बेरोजगारी ने असंतोष को और भड़काया है। इसके बावजूद, यह भी सच है कि आंतरिक संकट का समाधान बाहरी दबावों से नहीं निकल सकता। ईरान की स्थिरता और भविष्य उसके भीतर होने वाले संवाद और सुधारों पर निर्भर करेगा। यदि सत्ता वास्तव में देश की एकता और सुरक्षा चाहती है, तो उसे युवा वर्ग की आकांक्षाओं, महिलाओं की स्वतंत्रता और आर्थिक सुधारों की मांगों को गंभीरता से समझना होगा। केवल धार्मिक वैधता और दमन के सहारे लंबे समय तक शासन चलाना कठिन होता जा रहा है, खासकर उस दौर में जब सूचना और विचारों की सीमाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। भारत के लिए ईरान की मौजूदा स्थिति विशेष महत्व रखती है। ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी अहम हैं। ऐसे में भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों में संतुलन और सावधानी दोनों बरतनी होगी।

विदेश नीति के चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरता देश

> देश के लिए यह दौर विदेश नीति के मामले में चुनौतीपूर्ण है। विश्व स्तर पर यही स्थिति है। सबसे शक्तिशाली भागीदार अमेरिका के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध सबसे खराब दौर में हैं। जाहिर वजह तो टैरिफ व रूसी तेल खरीद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को एक पुराने मित्र देश और उभरती क्षेत्रीय ताकत की भी परवाह नहीं।

वर्ष 1998 में भारत द्वारा किए परमाणु परीक्षणों के बाद -जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे और परस्पर संवाद लगभग बंद हो गया था- यह पहली बार है जब अपने सबसे शक्तिशाली इस भागीदार के साथ भारत के संबंध खतरनाक रूप से नए निचले स्तर पर हैं। पिछले कुछ दिनों में, व्हाइट हाउस के उच्चतम गलियारों से तंज कसे गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक निवेदन करने वाले के रूप में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा : 'सर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं'। हां, माना जाता है कि अमेरिका की 'महान श्वेत आशा' ने उत्तर दे दिया।

पिछली बार जब एक प्रधानमंत्री -डॉ. मनमोहन सिंह- को एक अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष विनीत जैसा पाया गया था (2008 में उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कहा : 'भारत आपसे प्यार करता है'), तो देश में गुस्से का विस्फोट होना वाजिब था। सिर्फ 24 घंटे पहले, विदेश मंत्रालय ने मोदी द्वारा कही कथित बात को खारिज कर दिया। लेकिन संबंधों का यूं रसातल में जाते देखना बहुत बुरा लगा।

एक चमकदार अतीत से जुड़ी अद्वितीय और महान सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय अभिजात वर्ग का अमेरिका द्वारा जिस प्रकार उपहास उड़ाया जा रहा है, महज इसलिए कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की हिम्मत दिखाई- इस मामले में, कुछ अमेरिकी कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने से इंकार करना और सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने से मना करना -वह बहुत परेशान करने वाला है। जैसा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने एक पत्रकार से कहा, अमेरिकी प्रशासन ने भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमति देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी थी। इसके सिलसिले में मोदी को व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को फोन कर समझौते पर हस्ताक्षर की रजामंदी जाहिर करनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने फोन कॉल नहीं की।

आखिरकार, जब भारतीय पक्ष ने संपर्क किया, तो लटनिक ने उनसे कहा : 'बहुत देर हो चुकी है'। निश्चित रूप से, इसमें कुछ भी नया नहीं। भारत तो विशेष रूप से पश्चिमी नेताओं के सम्राटों की तरह पेश आने और अपना दबदबा दिखाए जाने का आदी है। विदेश मंत्रालय के अंदर, और बाहर भी, हर कोई उस दोगलेपन को समझता है जो बड़ी शक्तियों द्वारा खासकर शीत युद्ध के दौरान बरता जाता रहा, मीडिया ने उन्हें बेनकाब करने में कमी नहीं छोड़ी।

समस्या यह है कि कम से कम पिछले 20 सालों से, भारत सोचता था कि वह अमेरिकियों के साथ खड़ा है। हमने उनका हास-परिहास अपनाया, हमारे बच्चे उनके कॉलेजों में गए -भारतीय माता-पिता ने अपना पेट काटकर उन्हें वहां भेजने के वास्ते डॉलर खरीदने के लिए बचतें की- और हमारी आईटी विशेषज्ञ पीढ़ी ने अमेरिका को बारंबार महान बनाने के लिए एचवन-बी वीजा लगवाया। हम बराबरी के थे। या कम से कम हम ऐसा सोचते रहे।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, जोकि मोदी मंत्रिमंडल के सबसे समझदार लोगों में से एक हैं, पुराने भारत के नए भारत में रूपांतरित होने में भूमिका निभा चुके हैं। भारत के शीर्ष राजनयिकों में से एक होने के नाते उन्हें दोनों पक्षों के लोगों से दोस्ती करने का प्रशिक्षण प्राप्त है। जयशंकर के पिता के. सुब्रमण्यम ने तो 1971 में, बांग्लादेश युद्ध से पहले,पाकिस्तान के प्रति अमेरिका के 'अत्यधिक झुकाव' के लिए तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को खरी-खरी सुनाई थी (सुब्रमण्यम ने किसिंजर से पूछा था, आप पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं जबकि पाक सेना द्वारा नरसंहार से बचने के लिए लाखों पूर्वी पाकिस्तानी नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं, करीब 1 करोड़, और क्या आपको यह भी याद नहीं कि आपके अपने समुदाय यानि यहूदियों ने हिटलर के हाथों क्या झेला था?)।

नई वैश्विक व्यवस्था में, ट्रंप से हिल चुकी दुनिया के सामने भारत की विलक्षण स्थिति को, बतौर एक प्राचीन राष्ट्र जिसका लंबा औपनिवेशिक अतीत है, की स्थिति समझाने को जयशंकर एकदम उपयुक्त हैं। तो गलती कहां रही? ट्रंप का अमेरिका, मोदी के भारत का उपहास क्यों कर रहा , जबकि हम दोनों को एक पाले में होना चाहिए था, खासकर जब दुनिया को चीन से बचाने की कोशिश में हमारी ओर देखा जा रहा था? हमारे नए बेहतरीन दोस्त हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? इसके कई जवाब हैं, कुछ खुशगवार, कुछ उतने नहीं।

पहला, ट्रंप का अहंकार- उन्हें लगता है दुनिया को स्थाई तौर पर उनकी पिछलग्गू बन जाना चाहिए। लेकिन जब मोदी ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ट्रंप को कॉल करने से इंकार किया, तो अमेरिकियों ने अलग ढंग से दबाव बनाया– कहा कि अब ऐसा कोई समझौता नहीं हो सकता, और रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 500 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

नतीजतन, भारत इतना बेचैन गया कि बाकी चीज़ों के अलावा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका द्वारा धरपकड़ की निंदा करने से परहेज़ रखा। 'क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता', वे शब्द जो दशकों तक भारत के लिए नैतिकता का नारा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए उसकी निंदा करने के लिए भी किया गया था, वे अमेरिका के मामले में त्याग दिए गए।

दूसरा, यह और भी स्पष्ट होता जा रहा कि ट्रंप की विश्व दृष्टि में भारत की प्रासंगिकता नहीं है। उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं – जैसा कि पिछले कई दशकों में अमेरिकी सरकारें, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की वह सरकार भी शामिल है, जिसने 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत को एक तरह से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के क्लब में शामिल कर लिया था – कि भारत को मजबूत किया जाए ताकि वह चीन को रोकने वाली स्थानीय ताकत बन पाए। ट्रंप चीन के उद्भव से चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने सरेआम कह दिया कि चीन से वे खुद सीधे निपटेंगे।

तीसरा, ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं कि भारत, जो एक पुराना दोस्त, भागीदार और उभरती हुई क्षेत्रीय शक्ति है, वह नाराज़ हो जाएगा। उन्हें यह भी याद नहीं कि 2019 में मोदी ने ट्रंप के चुनाव अभियान में भारतीय प्रवासियों को 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' के नारे के साथ उनका समर्थन करने के लिए कहकर मदद की थी। कहा जा रहा है कि ट्रंप यह नहीं भूल पा रहे कि जब मोदी 2024 में बाइडेन से मिलने अमेरिका आए थे तब उनसे मिलने से इंकार कर दिया था। उन्हें इस तथ्य से नफरत है कि भारत ने सार्वजनिक तौर पर कई बार इस बात से इनकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर गतिरोध को खत्म करने में ट्रंप ने कोई मध्यस्थता की थी।

आज विदेश नीति के मामले में भारत चिंताजनक स्थिति में है। अमेरिकी भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चीन उत्तरी सीमा पर मौके की तलाश में ललचाई नजरें गड़ाए है। बांग्लादेश, वह मुल्क जिसे आजादी दिलाने में भारत ने मदद की, इससे नाराज़ है कि उसका पसंदीदा क्रिकेटर अवांछित बना दिया –बांग्लादेश ने आगामी टी-20 विश्व कप दौरान भारत में मैच न खेलने का फैसला किया है। भारत का दुश्मन, पाकिस्तान, अमेरिकियों के करीब आ रहा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान का पहला आधिकारिक दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र शायद ही वेनेजुएला के मामले में भारत के रवैए को भूल पाएं। नेपाल भी संकट में है।

अब बचे रूस, पश्चिमी यूरोप, इस्राइल और ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अगले हफ़्ते दिल्ली आ सकते हैं। शायद भारत राजनयिक खाई से बाहर निकलने की शुरुआत उनके साथ संबंध बढ़ाकर कर सकता है। लेकिन फिर यहां दूसरी समस्या है : अगर ऐसा होता है, तो ट्रंप और भी ज़्यादा खफ़ा हो सकते हैं।

प्रेरणा

अटूट संकल्प की राह पर चलकर गढ़ी जाती है सफलता की पहचान

जीवन में सफलता को लेकर हर व्यक्ति के मन में अलग-अलग कल्पनाएँ होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और गहरी लगन से जन्म लेती है। जो लोग महान कहलाते हैं, उनके जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी कभी साधारण थे, असफलताओं से जूझे थे और संदेहों के अंधेरे से गुज़रे थे। आइंस्टीन से जुड़ी यह प्रेरक घटना इसी शाश्वत सत्य को उजागर करती है कि लगन वह शक्ति है, जो कमजोरियों को ताकत में बदल देती है और व्यक्ति को उसकी सीमाओं से आगे ले जाती है।

आमतौर पर लोग यह मान लेते हैं कि महान वैज्ञानिक, कलाकार या नेता बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। वे यह नहीं देखते कि उन उपलब्धियों के पीछे कितनी बार असफलता, निराशा और संघर्ष छिपा होता है। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक का यह स्वीकार करना कि उन्हें गणित से डर लगता था और वे इस विषय में कई बार असफल हुए, इस भ्रम को तोड़ देता है कि महानता जन्म से मिलती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि डर और कमजोरी किसी को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उनसे लड़ने का साहस ही व्यक्ति को महान बनाता है।

जब कोई व्यक्ति किसी विषय या कार्य में बार-बार असफल होता है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उपहास, आलोचना और तुलना उसे भीतर से तोड़ने लगती है। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और अपनी असफलता को भाग्य या परिस्थितियों के सिर मढ़कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन लगन रखने वाला व्यक्ति इन सबके बीच भी रुकता नहीं है। वह स्वयं से प्रश्न करता है, अपने भीतर झांकता है और यह समझने की कोशिश करता है कि कमी कहाँ है। यही आत्ममंथन आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। आइंस्टीन ने भी यही किया। उन्होंने गणित से भागने के बजाय उसका सामना करने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह सफर आसान नहीं रहा होगा। सवाल कठिन लगे होंगे, गलतियाँ हुई होंगी और निराशा ने कई बार घेरा होगा। लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। रोज़ थोड़ा-थोड़ा सीखने की आदत ने धीरे-धीरे कठिनाई को सरलता में बदल दिया। जिस विषय से कभी डर लगता था, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि निरंतर लगन का परिणाम था।

लगन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करती है। उत्साह तो हर किसी में होता है, लेकिन वह जल्दी खत्म भी हो जाता है। असली परीक्षा तब होती है, जब उत्साह कम हो जाए और रास्ता कठिन लगने लगे। ऐसे समय में केवल लगन ही व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह उसे सिखाती है कि सफलता एक लंबी यात्रा है, जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आज के समय में त्वरित सफलता की चाह ने लोगों को अधीर बना दिया है। हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है और जब अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, तो निराश होकर प्रयास छोड़ देता है। लेकिन वास्तविक जीवन में कोई भी उपलब्धि रातोंरात नहीं मिलती। हर सफलता के पीछे अनगिनत असफल प्रयास, सीख और अनुभव छिपे होते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत भी वर्षों के अध्ययन, प्रयोग और धैर्य का परिणाम थे। यदि उन्होंने शुरुआती असफलताओं के कारण हार मान ली होती, तो विज्ञान का इतिहास शायद कुछ और ही होता।

लगन व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। जब कोई व्यक्ति बार-बार प्रयास करता है और धीरे-धीरे सुधार देखता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। यह विश्वास उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लगन केवल लक्ष्य को पाने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया भी है। यह व्यक्ति को अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होते हैं।

अक्सर लोग परिस्थितियों को दोष देकर अपने प्रयासों की कमी को छिपाने की कोशिश करते हैं। संसाधनों की कमी, अवसर न मिलना या दूसरों का साथ न होना—ये सभी बातें सच हो सकती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने इन बाधाओं के बावजूद लगन नहीं छोड़ी, उन्होंने असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कीं। लगन व्यक्ति को परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देती है।

लगन का अर्थ यह भी नहीं कि व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य में डूबा रहे और बाकी सब कुछ भूल जाए। इसका अर्थ है संतुलन के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना। छोटे-छोटे प्रयास, रोज़ की मेहनत और सीखने की ललक मिलकर बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। यही कारण है कि लगन रखने वाले लोग भले ही धीरे आगे बढ़ें, लेकिन उनकी सफलता टिकाऊ होती है।

आइंस्टीन की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक विकास संभव होता है। लगन इसी सुधार की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है और व्यक्ति को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुँचने में मदद करती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि महानता का कोई रहस्यमय सूत्र नहीं है। इसका एक ही मंत्र है—लगन। यह मंत्र सरल है, लेकिन इसका पालन करना कठिन है। जो व्यक्ति इस कठिन मार्ग पर डटा रहता है, वही समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाता है। आइंस्टीन की तरह हर कोई विश्व-प्रसिद्ध वैज्ञानिक न बने, यह आवश्यक नहीं, लेकिन लगन के सहारे हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, संतोष और आत्मगौरव अवश्य प्राप्त कर सकता है। यही लगन की असली जीत है और यही जीवन की सच्ची उपलब्धि।

चीन से क्या हम भाषायी बोध सीख सकते हैं

हिंदी के संदर्भ में देखें तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच शाब्दिक ही नहीं, भावात्मक फर्क भी है। फिर भी एक बड़ा वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा भी मानता है। यही वजह है कि हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के नौंवे महीने की दस्तक के साथ ही, हर सरकारी दफ्तर राजभाषा पखवाड़े या महीने को लेकर उत्साह से भर उठता है। कुछ ऐसा ही पड़ोसी चीन में भी अब होता नजर आ रहा है। अब वहां सितंबर का तीसरा सप्ताह 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि' को समर्पित होगा। भारत और चीन के सितंबर महीने के भाषायी उत्साह में एक अंतर रहेगा, राष्ट्रभाषा बनाने की आस में हिंदी के राजभाषा ओहदे को याद किया जाएगा, जबकि चीन अपनी मंदारिन भाषा को बाकायदा राष्ट्रभाषा के तौर पर और आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होगा।भाषायी चिंतन और व्यवहार को लेकर भारत और चीन को लेकर तकरीबन एक ही सोच है। भारत में एक मानस ऐसा है, जिसे हिंदी की कीमत पर भी पर अंग्रेजी स्वीकार्य है। यह धारा मानती है कि वेगवान आर्थिक विकास की वजह से चीन का भाषायी व्यवहार भी इसी भारतीय मानस की तरह बदल चुका है। बेशक चीन ने अंग्रेजी सीखने-सिखाने की दिशा में भरपूर निवेश किया है। अपनी आर्थिक ताकत के चलते पश्चिम के नामी विश्वविद्यालयों में चीनी सत्ता प्रतिष्ठान अपने लिए अध्ययन पीठ स्थापित कर चुका है। गौर करने की बात है कि उसने यह सब अलग और अतिरिक्त अनुशासन और ज्ञान के साधन के तौर पर किया है, भारत की तरह अपनी भाषा, विशेषकर हिंदी की कीमत पर ऐसा नहीं किया है। अंग्रेजी का पहला वैश्विक विस्तार ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौर में हुआ और दूसरी बार उसका प्रसार रीगन-थैचर की जोड़ी के आर्थिक उदारीकरण के बढ़ते कदमों के साथ हुआ। इस संदर्भ में चीन और भारत के भाषायी चिंतन और व्यवहार फर्क साफ नजर आता है। पिछली सदी के अस्सी के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख देंग झिआओपिंग ने आर्थिक खुलेपन की नींव रखी। यह 1978 का साल था। इसके ठीक दो साल बाद भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने भी धीरे-धीरे इंस्पेक्टर राज कम करने की शुरूआत की। उनकी उदारीकरण की सोच को राजीव गांधी ने परवान चढ़ाया। 1991 के आम चुनावों के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पहली बार समाजवादी आर्थिक नीतियों के बरक्स उदारीकरण का वादा किया। तब से अब तक की दोनों देशों की आर्थिक विकास यात्रा को देखें तो अंतर साफ नजर आता है। चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। उसकी तेज आर्थिक यात्रा के समानांतर अंग्रेजी का विस्तार नहीं दिखता। जबकि भारत में इसके ठीक उलट नजारा दिखता है। उदारीकरण के बरक्स दोनों देशों के भाषायी चिंतन में भी फर्क नजर आता है। यह फर्क ही है कि चीन अब अपनी मंदारिन भाषा और उसकी लिपि को लेकर सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते को समर्पित कर रहा है। चीन की सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था 'राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा' की स्थाई समिति द्वारा बीते 27 दिसंबर को इससे जुड़ा कानून पारित करना इसी सोच का प्रतीक है। इस कानून में हर वर्ष सितंबर के तीसरे सप्ताह को 'राष्ट्रीय सामान्य भाषा और लिपि संवर्धन एवं प्रचार सप्ताह' के रूप में मनाना तय किया गया है। यह कानून पुराने राष्ट्रीय भाषा कानून में संशोधन के बाद आया है। चीन में दो तरह की मंदारिन का प्रयोग होता है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। इस कानून में दोनों तरह की भाषाओं का ध्यान रखा गया है।

चीन अपनी भाषा और लिपि को अपने राष्ट्र का प्रतीक मानता है। चीन में इन दिनों प्रौद्योगिकी और डिजिटल जगत में लगातार प्रगति हो रही है। यहां ऑडियो-विजुअल प्रोग्रामिंग और गेमिंग भी बढ़ी है। चीन का भाषायी कानून इन सबमें इस्तेमाल होने वाली भाषा के साथ कदमताल करने का प्रयास है। कहा जा सकता है कि चीनी राष्ट्रभाषा और लिपि कानून में यह संशोधन तेजी से विकसित हो रही संचार प्रौद्योगिकियों और ऑनलाइन सामग्री के विस्तार के बीच भाषा के मानकीकरण को मजबूत करने की कोशिश है। इस कानून में साइबरस्पेस प्रशासन को लेकर भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत अब ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वेब सीरीज, ऑनलाइन फिल्मों, ऑनलाइन गेम और अन्य डिजिटल प्रकाशनों में मानक चीनी भाषा यानी मंदारिन और मानकीकृत चीनी अक्षरों को मूल भाषा के रूप में उपयोग करना जरूरी होगा। इसके साथ ही चीन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स आदि के साइनबोर्ड, लेबल या प्रमोशनल मैटीरियल में विदेशी भाषाओं के साथ ही मानक चीनी भाषा भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसकी तुलना में भारतीय राष्ट्रभाषा और आधुनिक प्रौद्योगिकी संग उसके तालमेल पर नजर डालें साफ फर्क नजर आता है। भारत अब भी राष्ट्रभाषा से दूर है। हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाली ताकतों के सुर भी अब धीमे पड़ते जा रहे हैं। लेकिन चीन अपने आर्थिक उदारीकरण के बावजूद अपनी भाषा की ओर लौटता नजर आ रहा है। इसके साथ ही चीन के भाषायी आंकड़ों पर भी नजर डालना जरूरी है। यहां की करीब 80 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी मंदारिन बोल सकती है। चीन में करीब 97.33 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इनमें करीब 95 प्रतिशत से ज़्यादा लोग मानक चीनी अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चाइना इंटरनेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते जून तक चीन में एक अरब 12 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार, चीन में इंटरनेट इस्तेमाल की दर 79.7 प्रतिशत तक पहुँच गई है। भाषायी कानून में इन आंकड़ों के मद्देनजर सरकारी और पब्लिक सर्विस वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए भी सरकारी नियमों और मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय मानक भाषा का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। इस कानून का लक्ष्य "चीनी राष्ट्र के प्रति मजूबत सामुदायिक भावना का विकास "और "सांस्कृतिक आत्मविश्वास की मज़बूती" है।

अभियान

अलाव की लौ में धड़कता जीवन, परंपरा और सामूहिक आनंद का उत्सव

कुछ पर्व केवल कैलेंडर की तारीख़ों तक सीमित नहीं रहते, वे समाज की चेतना, स्मृति और जीवन-दर्शन का हिस्सा बन जाते हैं। लोहड़ी ऐसा ही पर्व है, जो पंजाब की मिट्टी में केवल बोया नहीं गया, बल्कि पीढ़ियों से उसमें सांस लेता आया है। यह पर्व मौसम के बदलाव का संकेत भर नहीं देता, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के गहरे रिश्ते, सामूहिकता की भावना और जीवन की ऊर्जा को उत्सव में बदल देता है। लोहड़ी की आग केवल सर्दी से राहत देने का साधन नहीं होती, वह भीतर की ठिठुरन, अकेलेपन और निराशा को भी जलाकर नई उम्मीद की लौ प्रज्वलित करती है। यही कारण है कि लोहड़ी का महत्व केवल एक सांस्कृतिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि वह पंजाबी समाज की जीवंत आत्मा का प्रतीक बन चुकी है। हर साल आमतौर पर 13 जनवरी को मनाया जाने वाला यह पर्व उस समय आता है, जब शीत ऋतु अपने चरम पर होती है और सूर्य उत्तरायण होने की दहलीज़ पर खड़ा होता है। यह संधिकाल केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि कृषि प्रधान समाज के लिए आशा और भरोसे का संकेत होता है। खेतों में रबी की फसल लहलहाने लगती है, किसान के मन में मेहनत के फल की उम्मीद जगती है और जीवन एक नए चक्र की ओर बढ़ता है। लोहड़ी इसी परिवर्तन को सामूहिक उल्लास में ढाल देती है। आग के चारों ओर जमा लोग तिल, गुड़, मूंगफली और मक्के की आहुति देते हैं, मानो प्रकृति को धन्यवाद कह रहे हों और आने वाले समय के लिए समृद्धि का आह्वान कर रहे हों।

लोहड़ी की आत्मा सामूहिकता में बसती है। यह ऐसा पर्व नहीं जिसे अकेले मनाया जा सके। अलाव तभी अर्थपूर्ण होता है, जब उसके चारों ओर लोग हों, गीत हों, हंसी हो और आपसी संवाद हो। जैसे ही अलाव प्रज्वलित होता है, व्यक्ति अपनी पहचान, हैसियत और भेदभाव भूलकर समूह का हिस्सा बन जाता है। अमीर-गरीब, छोटे-बड़े, उम्र और वर्ग के फर्क उस आग की लौ में पिघल जाते हैं। यह सामूहिक अनुष्ठान व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का उत्सव भी है। शायद यही कारण है कि आधुनिक समय की व्यस्तता और एकाकी जीवनशैली के बीच भी लोहड़ी का आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हुआ है।

आग का प्रतीकात्मक महत्व भारतीय संस्कृति में सदियों से रहा है। उसे शुद्धता, ऊर्जा और परिवर्तन का स्रोत माना गया है। लोहड़ी की आग भी इसी परंपरा का विस्तार है। जब लोग अलाव की परिक्रमा करते हैं, तो वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता, भय और थकान को आग में समर्पित कर देता है। यह आग जैसे कहती है कि पुराना बीत गया, अब नए सिरे से जीवन को अपनाओ। यही कारण है कि लोहड़ी केवल उत्सव नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक नवीनीकरण का पर्व भी है। लोकगीत लोहड़ी की आत्मा में प्राण फूंकते हैं। 'सुंदर, मुंदरिये हो' की गूंज के बिना लोहड़ी की कल्पना अधूरी है। इन गीतों में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास और नैतिकता की गहरी परतें छिपी हैं। दुल्ला भट्टी का नाम लोहड़ी के गीतों में बार-बार आता है, जो केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि पंजाबी लोकचेतना का नायक है। उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, शोषितों की रक्षा की और बेटियों को सम्मान दिया। लोहड़ी की रात जब ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धा अपने शिखर पर होते हैं, तब भी दुल्ला भट्टी का स्मरण यह याद दिलाता है कि उत्सव और नैतिक मूल्य साथ-साथ चल सकते हैं। यह पर्व बताता है कि संस्कृति केवल नाच-गाने का नाम नहीं, बल्कि साहस, करुणा और न्याय की विरासत भी है।

लोहड़ी की खास बात यह भी है कि इसका खानपान सादगी से भरा होता है। तिल, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का जैसे खाद्य पदार्थ न केवल शीत ऋतु के अनुकूल हैं, बल्कि ग्रामीण जीवन की सरलता और प्रकृति से जुड़ाव को भी दर्शाते हैं। यह पर्व दिखाता है कि उत्सव का आनंद भव्यता में नहीं, बल्कि अपनापन और साझा स्वाद में छिपा होता है। आधुनिक समय में भले ही मेन्यू बदल गए हों, लेकिन लोहड़ी की आत्मा आज भी उसी सादगी में बसती है।

लोहड़ी का सामाजिक स्वरूप तब और गहरा हो जाता है, जब किसी परिवार में नई बहू या नवजात शिशु की पहली लोहड़ी मनाई जाती है। यह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे समाज द्वारा नए जीवन के स्वागत का उत्सव होता है। उपहार, गीत और सामूहिक सहभागिता यह संदेश देती है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, समाज उसके साथ खड़ा है। यही सामूहिकता लोहड़ी को केवल पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कार बना देती है।

इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण इसका अल्हड़पन है। यहां कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावटी अनुशासन नहीं। जो मन में है, वही नृत्य है, वही गीत है, वही उल्लास है। पंजाबी संस्कृति जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा देती है और लोहड़ी इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। यहां हंसी खुलकर आती है, आवाज़ बुलंद होती है और शरीर ढोल की थाप पर खुद-ब-खुद थिरकने लगता है।

आज जब दुनिया तेज़ी से शहरीकरण और तकनीक की ओर बढ़ रही है, तब भी लोहड़ी की लोकप्रियता कम नहीं हुई। गांवों से निकलकर यह पर्व शहरों के अपार्टमेंट, सोसाइटियों और विदेशी धरती तक पहुंच गया है। प्रवासी पंजाबी समुदाय के लिए लोहड़ी अपनी जड़ों से जुड़े रहने का माध्यम बन गई है। यह पर्व उन्हें याद दिलाता है कि चाहे भौगोलिक दूरी कितनी भी हो, सांस्कृतिक पहचान दिल से दूर नहीं होती।

लोहड़ी का उत्सव यह भी सिखाता है कि सामूहिक आनंद और सामाजिक जुड़ाव मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जब व्यक्ति अकेलेपन और तनाव से जूझता है, तब ऐसे पर्व उसे रुककर सांस लेने, मुस्कुराने और एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर देते हैं। लोहड़ी की आग केवल लकड़ियां नहीं जलाती, वह दिलों के बीच की दूरी भी पिघलाती है।

अंततः लोहड़ी केवल एक क्षेत्रीय पर्व नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। यह पर्व सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। सामूहिकता में शक्ति है, सादगी में आनंद है और परंपरा में भविष्य की राह छिपी है। अलाव की लौ में जब गीत, नृत्य और हंसी घुल-मिल जाते हैं, तब लोहड़ी केवल एक रात का उत्सव नहीं रह जाती, बल्कि पूरे वर्ष के लिए जीवन ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यही लोहड़ी की असली पहचान है—जीवन, परंपरा और सामूहिक आनंद का जीवंत उत्सव।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

वीजीआरसी-2026

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में 5.78 लाख करोड़ रुपए के 5492 एमओयू संपन्न : कैबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

- विकसित भारत@2047 के संकल्प में सौराष्ट्र–कच्छ बनेगा देश का ग्रोथ इंजन : मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी
- श्री जीतूभाई वाघाणी ने 15 जनवरी तक चलने वाली एग्जीबिशन का अधिक से अधिक लाभ लेने का औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों से किया अनुरोध
- सौराष्ट्र के उद्योगकार न्यू एज टेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश कर आगे बढ़ें : कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया का आह्वान
- 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' सौराष्ट्र कच्छ की क्षमता को दुनिया के समक्ष उजागर करने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनी : कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया
- वीजीआरसी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एमएसएमई और प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया

(जीएनएस)। राजकोट : राजकोट स्थित मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में आयोजित दो दिवसीय 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस-कच्छ और सौराष्ट्र' का सोमवार को समापन हुआ। कैबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5.78 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 5492 समझौता ज्ञापन (एमओयू) होने की घोषणा की।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि वर्ष 2047 तक सौराष्ट्र और कच्छ को विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ठोस रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब वर्ष 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, तब उन्हें अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके अचल विश्वास और विजन के कारण आज गुजरात और भारत विकास की लंबी छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जिनसे दुनिया भर की प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयां मिलने को आतुर होती हैं, यह दर्शाती है कि सौराष्ट्र और कच्छ का विकास उनके लिए कितना मायने रखता है। मंत्री श्री वाघाणी ने वाइब्रेंट गुजरात की ऐतिहासिक यात्रा और सफलता के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात के दौरान केवल 66 हजार करोड़ रुपए के 80 एमओयू किए गए थे, जिसके मुकाबले आज राजकोट में आयोजित इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में ही 5.78 लाख करोड़ रुपए के 5492 एमओयू संपन्न हुए हैं। ये आंकड़ें और अनेक देशों की सहभागिता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर अटूट विश्वास को दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे आयाम साकार हो रहे हैं, जिसका सीधा लाभ गुजरात के उद्योगपतियों और इकाइयों को मिल रहा है।

उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न सेक्टरों में हुई गहरी चर्चाओं के उद्योगों के लिए मार्गदर्शक साबित होने का विश्वास व्यक्त करते हुए औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में आगामी 15 जनवरी तक चलने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन का लाभ लेने का अनुरोध किया। अंत में, उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जब भारत विश्वगुरु के स्थान पर विराजेगा, तब सौराष्ट्र और कच्छ उसके मुख्य ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेंगे।

इस अवसर पर राज्य के पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने कहा कि 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की क्षमता को दुनिया के समक्ष उजागर करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनी है।

विभिन्न ऐतिहासिक किस्सों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कच्छ और सौराष्ट्र के लोगों की नस-नस में उद्यमिता भरी है। एक समय था जब सौराष्ट्र के नाविक समंदर पर राज करते थे।

उन्होंने सौराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक विशेषताओं का परिचय देते हुए कहा कि राज्य का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी कौशल से भरा है और इसमें सौराष्ट्र का दबदबा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ बेल्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र बनने जा रहा है। देश और राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात राज्य वर्ष 2027 में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का हब बन जाएगा।

इस अवसर पर उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र के उद्योगपतियों से न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उद्योग विभाग की सचिव सुश्री ममता वर्मा ने स्वागत भाषण में सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को गौरवपूर्ण क्षण करार देते हुए कहा कि पिछले दो दिनों में 'स्केल और स्किल' के समन्वय के साथ उद्यमियों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। बीटूबी, बीटूजी, रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट और 50 से अधिक सेमिनारों के आयोजन से युवा पीढ़ी को भी एक नई दिशा मिली है।

इस अवसर पर उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की सफल यात्रा की विस्तार से जानकारी दी।

मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री केतन मारवाड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया है कि भारत आज विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आयोजित कॉन्फ्रेंस में 24 देशों के प्रतिनिधियों और 4000 उद्यमियों की उपस्थिति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों के करकमलों से 'कच्छ एंड सौराष्ट्र : एंकरिंग गुजरात्स विजन' पुस्तक का विमोचन किया गया।

इस मौके पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभिन्न एमएसएमई के उद्योगकारों, हस्तकला कारीगरों और उद्योग विभाग का पुरस्कार के साथ सम्मान किया गया, जबकि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के संचालकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका भी सम्मान किया गया।

समापन समारोह में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री हसमुख अढिया, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री जयंती रवि, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी, विधायक सर्वश्री डॉ. दर्शिताबेन शाह, रमेशभाई टीलाळा, एलएंडटी के सीईओ श्री सिद्धार्थ गुप्ता, ज्योति सीएनसी के चेयरमैन श्री पराक्रमसिंह जाडेजा, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापक श्री जीतूभाई चंदाराणा, राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री वी.पी. वैष्णव, अग्रणी उद्योगकार, व्यापार-उद्योग जगत के प्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।

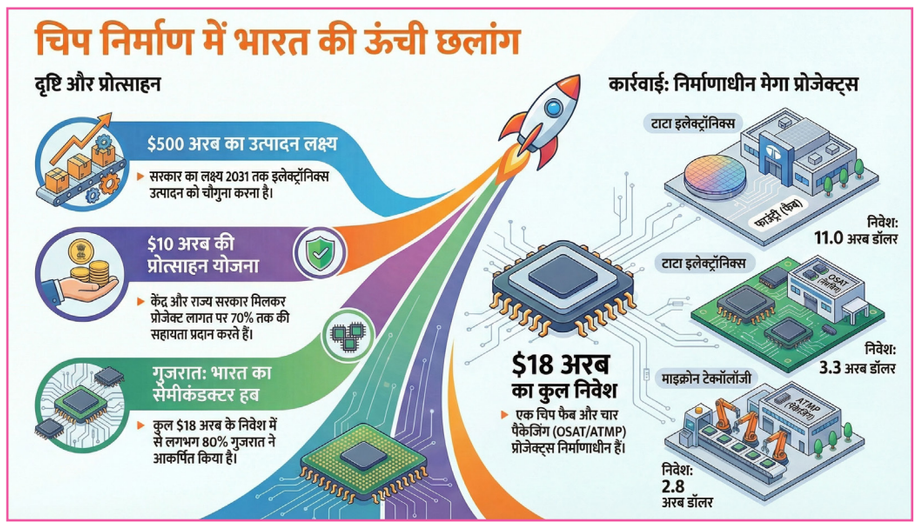

जर्मनी के स्टेट सेक्रेटरी श्री स्टिफन राउएनहोफ के नेतृत्व में जर्मन बिजनेस डेलीगेशन की मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक

- मुख्यमंत्री के जर्मन उद्योगों के निवेशों को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने के दिशानिर्देश
- भारत के जीडीपी ग्रोथ में गुजरात के 8 प्रतिशत से अधिक तथा महत्वपूर्ण योगदान से प्रभावित हुआ जर्मन प्रतिनिधिमंडल
- मुख्यमंत्री ने आपसी सहभागिता से ग्रोथ रेट को ऊँचाई पर ले जाने की मंशा व्यक्त की
- मुख्यमंत्री ने जर्मनी की प्रिसिजन इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक्सपर्टीज का लाभ गुजरात को मिलने की अपेक्षा व्यक्त की

(जीएनएस)। गांधीनगर : जर्मनी के स्टेट सेक्रेटरी श्री स्टिफन राउएनहोफ के नेतृत्व में जर्मन बिजनेस डेलीगेशन ने सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह डेलीगेशन भारत-जर्मन सीईओ फोरम में सहभागी होने के लिए भारत-गुजरात की यात्रा पर आया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की उपस्थिति में आयोजित सीईओ फोरम की सफलता के लिए इस डेलीगेशन को अभिनंदन देने के साथ गुजरात में उनका स्वागत किया।

डेलीगेशन के सदस्यों ने गुजरात के देश के जीडीपी ग्रोथ में 8 प्रतिशत से अधिक का महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने पर प्रभावित होते हुए कहा कि वे विशेषकर एसएमई सेक्टर में बिजनेस एंड इकोनॉमी संबंध बढ़ाने को उत्सुक हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में अब देश के राज्यों के ग्रोथ रेट बढ़ाने की ओर आगे बढ़ने की भूमिका दी और इस संदर्भ में कहा कि जर्मनी के उद्योगों ने गुजरात पर जो भरोसा रखा है, उसे अधिक सुदृढ़ बनाकर आपसी सहयोग से हम अधिक प्रगति कर सकेंगे।

उन्होंने इस बैठक में चर्चाओं के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जर्मनी के साथ विश्वसनीय मित्र के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में गुजरात एवं जर्मनी के औद्योगिक संबंधों को अधिक गहराईपूर्वक तथा दीर्घावधि के लिए विकसित कर गुजरात में जर्मन कंपनियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अधिक वेग मिले; ऐसी हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री ने बैठक में जर्मन उद्योगों के निवेशों को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए हेल्प डेस्क शुरू करने के दिशानिर्देश भी दिए।

जर्मन स्टेट सेक्रेटरी श्री स्टिफन राउएनहोफ ने चर्चा के दौरान कहा कि जर्मनी अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सीफाई करना चाहता है, जिसमें गुजरात को उसकी पसंद बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एवं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में विद्यमान चुनौतियों का हल होना अपेक्षित है।

उन्होंने जोड़ा कि गुजरात एनर्जी सेक्टर में अग्रसर है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड तथा स्टोरेज की जर्मन टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज का सहयोग मिल सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 का जो विजन दिया है, उसमें गुजरात लीड लेने को सज्ज है। 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य के साथ-साथ विकसित गुजरात@2047 का रोडमैप तैयार कर 6 रीजनल ग्रोथ हब तथा वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से जिला स्तर पर फोकस सेक्टर भी तैयार किए गए हैं।

इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने गुजरात को पॉलिसी ड्रिवन स्टेट के रूप में विशिष्ट पहचान दिलाई है। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आदि सेक्टर स्पेशिफिक पॉलिसीज का लाभ लेकर जर्मनी के उद्योग स्वयं के अनुकूल सेक्टर्स में गुजरात के साथ सहभागिता कर सकते हैं। श्री पटेल ने अपेक्षा व्यक्त की कि प्रिसिजन इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी सेक्टर में जर्मनी की विशेषज्ञता का लाभ गुजरात को मिले।

इस डेलीगेशन के सदस्य तथा सीमेंस के सीईओ रोनाल्ड बुश ने भी गुजरात में एसएमई तथा अन्य उद्योग सप्लाई चेन का हिस्सा बनें या सप्लाई चेन डेवलप करने में उपयोग हो सकें; तत्संबंधी सुझाव दिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के साथ चर्चा में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों के जो 30 से अधिक उद्योगकार-निवेशक सहभागी हुए; उनमें डॉ. कार्ल बिल्जर, मैनेजिंग डाइरेक्टर, Delo industrieklebstoffe, ब्रुकनर टोकेंटेक्निक की सीईओ श्री रेजीना ब्रुकनर, वेबस्टो एसई के सीईओ श्री जोर्ग बुचहेम, टीकेएमएस एजी के एमडी श्री ओलिवर बर्कहार्ड, डॉ. वुल्फ ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर श्री एड्युर्ड रिचर्ड डोरेनबर्ग आदि शामिल हैं। इस डेलीगेशन के सभी सदस्यों ने गुजरात के आतिथ्य सत्कार की भी प्रशंसा की।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, एसजीएसटी आयुक्त श्रीमती आरती कँवर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुए।

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत राजकोट में 'सौराष्ट्र इकोनॉमिक रीजन' सेमिनार में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की विशेष उपस्थिति

2047 तक सौराष्ट्र की जीडीपी 600 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी : केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) की फलश्रुति के रूप में सोमवार को राजकोट में 'सौराष्ट्र इकोनॉमिक रीजन SaER – इकोनॉमिक मास्टर प्लान' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को अब क्षेत्रीय स्तर पर ले जाना भविष्य की जरूरतों को पहचानने की प्रधानमंत्री की अनूठी क्षमता का नतीजा है। इस दृष्टिकोण से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्लेटफॉर्म मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को एक नई गति मिलेगी। वाणिज्य मंत्री ने सौराष्ट्र के विकास के लिए तैयार किए गए 30 वर्षों के दीर्घकालिक इकोनॉमिक मास्टर प्लान की जानकारी देते हुए कहा कि क्लस्टर आधारित विकास मौजूदा समय की मांग है। इस प्लान के अंतर्गत राजकोट में इंजीनियरिंग और मेडिकल डिवाइस पार्क तथा जामनगर में पेट्रोकेमिकल्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें गुजरात की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषकर, 2047 तक सौराष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 11 से 12 गुना बढ़कर 600 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा और गुजरात 'विकसित भारत' के संकल्प का मुख्य आधार स्तंभ बना रहेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव श्री अजय भादू ने सौराष्ट्र के उद्यमियों से केवल 'सप्लायर' होने की सोच से आगे बढ़कर 'सिस्टम और सॉल्यूशन प्रोवाइडर' बनने का आह्वान किया। उन्होंने राजकोट के इंजीनियरिंग, मोरबी के सिरेमिक और जामनगर के एनर्जी क्लस्टर को ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, एयरोस्पेस और प्रिसिजन मैन्युफेक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।

सेमिनार में 'गुजरात राज्य परिवर्तन संस्था z- GRIT' की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुश्री एस. अपर्णा ने मास्टर प्लान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जबकि बंदरगाह और परिवहन विभाग के सचिव श्री राजेन्द्र कुमार ने सौराष्ट्र-कच्छ के बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसरों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री वी.पी. वैष्णव ने भी निवेशकों को इस क्षेत्र को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के विभिन्न तकनीकी सत्रों में देश और दुनिया के विशेषज्ञों ने रक्षा, एयरोस्पेस और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की। जिनमें महिंद्रा लाइफस्पेस के श्री विक्रम गोयल, JAFZA के श्री यूसुफ तांबावाला और पीडब्ल्यूसी इंजिया के श्री मोहम्मद अथर जैसे विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में उद्योग जगत के अग्रणियों ने सौराष्ट्र में रक्षा, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग और सिरेमिक क्षेत्र में निर्यात के अवसरों तथा लॉजिस्टिक्स के नजरिये पर भी प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव (योजना) सुश्री आद्रा अग्रवाल ने सभी महानुभावों का शाब्दिक स्वागत किया और प्रासंगिक विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ज्योति सीएनसी के श्री पराक्रमसिंह जाडेजा सहित अग्रणी उद्योगपति और निवेशक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मेर्ज ने गांधी आश्रम का दौरा किया

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मेर्ज ने महात्मा गांधीजी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी
- जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मेर्ज गांधी आश्रम की यात्रा से प्रभावित हुए

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने सोमवार को अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम का दौरा किया। इस अवसर पर दोनों महानुभावों ने महात्मा गांधीजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री तथा जर्मनी के चांसलर ने आश्रम में गांधीजी के निवास स्थान हृदय कुंज का भी दौरा किया तथा चरखा कातने की प्रक्रिया को देखा। गांधी आश्रम की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने गांधीजी के सादगीपूर्ण जीवन, आत्मनिर्भरता के संदेश तथा सत्य और अहिंसा के मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मेर्ज गांधी आश्रम के दौरे से प्रभावित हुए।

उन्होंने विजिटर्स बुक में मेसेज देते हुए कहा कि स्वतंत्रता की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के मन में महात्मा गांधी का अडिग विश्वास आज भी हमें प्रेरणा देता है। यह मानवीय विरासत भारत और जर्मनी के लोगों को मित्रता के माध्यम से एक साथ जोड़ती है। आज भी दुनिया में गांधीजी के उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं। गांधी आश्रम की इस यात्रा के अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, साबरमती आश्रम के अध्यक्ष श्री कार्तिकेय साराभाई, साबरमती आश्रम रीडेवलपमेंट कमिटी के अध्यक्ष श्री आई. पी. गौतम, अहमदाबाद जिला कलेक्टर श्री सुजीत कुमार तथा जर्मन डेलीगेशन व गांधी आश्रम से जुड़े महानुभाव उपस्थित रहे।

वीजीआर-एग्जीबिशन में रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट में 500 करोड़ रुपए के निर्यात को लेकर हुई बिजनेस इंक्वायरी

अमेरिका और कनाडा सहित 23 देशों के 53 खरीदारों और 1800 से अधिक स्थानीय विक्रेताओं ने लिया हिस्सा

(जीएनएस)। राजकोट : गुजरात रीजनल एग्जीबिशन में हॉल नंबर 1 में 'रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट' आकर्षण का केंद्र बन गई है। यहां भारत से विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स से वस्तुएं खरीदने के लिए 23 देशों से 53 अंतरराष्ट्रीय खरीदार आए हैं। अपने उत्पाद बेचने के लिए पूरे राज्य से 1800 से अधिक मैन्युफैक्चरर्स यहां पहुंचे हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के अपर महानिदेशक श्री सुविध शाह के अनुसार, इस बायर्स-सेलर्स मीट के जरिए स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पादन सीधे विदेश में बेचने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।

इस मीट का आयोजन गुजरात सरकार के इंडेक्स्ट-बी (iNDEXTb), उद्योग आयुक्त, एमएसएमई, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (RAMP), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO), केमिकल एंड एप्लाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (CAPEXIL), गुजरात ज्वैलरी प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJPEPC) ने मिलकर किया है।

इस मीट में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्री फूड, टाइल्स सिरेमिक, इंजीनियरिंग, ऑटो और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे क्षेत्रों को केंद्र में रखा गया है। इस मीट में अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रशिया, खाड़ी के देश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों सहित कुल 23 देशों से 53 अंतरराष्ट्रीय खरीदार, जबकि 22 स्थानीय खरीदार आए हैं। वहीं, पूरे राज्य से 1800 से अधिक विक्रेताओं ने अपने उत्पाद बेचने के लिए उत्साह दिखाया है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच 2200 से अधिक बैठकें हुई हैं, और दो दिनों में 1000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके साथ ही, लगभग 500 करोड़ रुपए के निर्यात की व्यावसायिक मांग भी आई है।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

सामग्री की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से DY.CMM-साबरमती, पश्चिम रेलवे, सामग्री की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित करता है।

क्र. सं.	निविदा नंबर	सामग्री का संक्षिप्त विवरण	मात्रा	ई-निविदा बंद होने की तारीख और समय	EMD राशि
1	71265016	KR-5 (ब्रेक वाल्व) [पार्ट नंबर: 90372] मेक: प्लासर, KNORR	03 नग	05/02/2026 11.00 AM	112310/-
2	71255598	ट्रैक लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट [प्लासर पार्ट नंबर: UD313.3000-SP.1668/1676] मेक: प्लासर	01 सेट	27/01/2026 11.00 AM	122130/-
3	71256693A	1) क्लैप पॉइंट लॉक 60KG (मोटे वेब स्विच के लिए) B.G. के लिए RDSO ड्राइंग नंबर RDSO/S 3395A, ALT-1 (मुख्यड्राइंग RDSO/S 3454 ALT-B) के अनुसार असेंबली का पूरा सेट 2) क्लैप पॉइंट लॉक 60KG (मोटे वेब स्विच के लिए) B.G. के लिए RDSO ड्राइंग नंबर RDSO/S 3395A, ALT-1 (मुख्यड्राइंग RDSO/S 3454 ALT-B) के अनुसार असेंबली का पूरा सेट	1) 120 सेट 2) 120 सेट	02/02/2026 11:00	132770/-

खरीद पर प्रतिबंध और निविदा की विस्तृत शर्तों वाली विस्तृत निविदा सूचना के लिए, कृपया **वेबसाइट** www.ireps.gov.in पर जाएं। मैनुअल ऑफ़र पर विचार नहीं किया जाएगा। ADI 253

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव – 2026, अहमदाबाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज ने पतंग उड़ाकर किया आईकेएफ-2026 का भव्य प्रारंभ

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट से सोमवार को 'अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव (आईकेएफ)-2026' का शुभारंभ कराया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज उपस्थित रहे। दोनों महानुभावों ने पतंग उड़ाकर इस महोत्सव का शुभारंभ कराया, जो भारत तथा जर्मनी के बीच सुदृढ़ राजनयिक संबंधों एवं मित्रता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज ने इस अवसर पर अहमदाबाद की पोल व हवेली की विशेष रूप से तैयार की गई स्थापत्य कला की प्रतिकृति को देखा। उत्तरायण केवल पतंगबाजी ही नहीं, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक पहचान समान उत्सव है। ऐसे में इस हेरिटेज वॉकवे पर पतंग म्यूजियम तथा आइकॉनिक फोटो वॉल भी बनाए गए हैं, जहाँ दोनों महानुभावों ने विभिन्न राज्यों की अलग-अलग कागज तथा बनावट की पतंगों के बारे में सूक्ष्मतापूर्वक जानकारी भी प्राप्त की। यहाँ पतंग बनाने वाले कारीगरों द्वारा पतंग बनाने की कला का जीवंत निदर्शन भी किया गया, जिसे महानुभावों ने रुचिपूर्वक देखा। इस अवसर पर गुजरात के बेडा रास (घड़ा रास) के अलावा; कुचिपुड़ी, भरत नाट्यम सहित नृत्यकला तथा मलखम जैसी प्राचीन अंग व्यायाम कला द्वारा विशेष प्रस्तुति के माध्यम से दोनों महानुभावों का स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त; इस अवसर पर गुजरात-राजस्थान के कुल लगभग 108 कलाकारों द्वारा सितार, सारंगी, वायलीन, मेंडोलिन, हार्मोनियम, बाँसुरी, ढोलक, तबला, मृदंग आदि विभिन्न वाद्यों के माध्यम से 'वंदे मारतम्', 'वैष्णजन' तथा जर्मन धुन बजाकर भारत व जर्मनी की मित्रता की प्रतीति कराई गई। उल्लेखनीय है कि गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (टीसीजीएल) द्वारा आयोजित इस रंगबिरंगी आकाशी महोत्सव में इस वर्ष 50 देशों के 135 अंतरराष्ट्रीय पतंगबाज तथा भारत के 13 राज्यों के 65 पतंगबाज अपनी भाँति-भाँति के रंगों और आकारों की पतंगों के साथ सहभागी हुए हैं। इसी प्रकार; गुजरात के 16 जिलों से 871 पतंगबाज भी उपस्थित रहकर कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, स्थानीय विधायक, महानगर पालिका के पदाधिकारी, राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव तथा अधिकारी उपस्थित रहे।

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रोत्साहक उपस्थिति

▸▸ अहमदाबाद के आकाश में छाया रंगों का उत्सव, साबरमती रिवरफ्रंट पर भारत के अलावा लगभग 50 देशों के 1000 से अधिक पतंगबाजों का जमावड़ा

▸▸ संगीत एवं नृत्य के अनूठे संगम से प्रधानमंत्री तथा जर्मन चांसलर का किया गया विशिष्ट स्वागत

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026 बना भारत-जर्मनी की मित्रता का प्रतीक

13 जनवरी की शाम संगीत तथा रंगों का अनूठा समन्वय सृजित होगा

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में 13 जनवरी मंगलवार को शाम 7 बजे 108 कलाकारों द्वारा भव्य सिम्फनी प्रदर्शन तथा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा कला एवं संगीत का अनुभव कराया जाएगा। इसमें लोक गायिका किंजल दवे द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, जबकि आकाश रंगबिरंगी रात्रि पतंगों से झिलमिला उठेगा।

आगंतुकों को कराया जाएगा गुजराती व्यंजन व हस्तकला का परिचय

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जैसे राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करने वाले आयोजनों के माध्यम से समग्र गुजरात की पहचान विश्व स्तर पर अग्रणी सांस्कृतिक एवं पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसे में आगंतुकों को गुजरात के व्यंजन तथा हस्तकला का परिचय कराने के लिए 25 हस्तकला स्टॉल और 15 फूड स्टॉल भी बनाए गए हैं।

लगभग 50 देशों के पतंगबाज इस महोत्सव में कला प्रदर्शित कर रहे हैं

अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ग्वाटेमाला, हंगरी, इंडोनेशिया, आयर्लैंड, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लेबनॉन, लिथुनिया, मलेशिया, मॉरीशस, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सिंगापुर, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम, स्लोवेनिया, बहरीन, नेपाल, तुर्की, जॉर्डन सहित कुल लगभग 50 देशों के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं।

स्वास्थ्य कारणों से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा इलाज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी को उन्हें दो बार अचानक बेहोशी के दौरे पड़े थे, जिसके बाद चिकित्सकों ने एहतियातन उन्हें एम्स में भर्ती कर व्यापक चिकित्सकीय जांच कराने की सलाह दी। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को बेहोशी के दौरे पड़ने के बाद पहले प्राथमिक स्तर पर जांच की गई थी, लेकिन उम्र और पूर्व में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए विस्तृत जांच को आवश्यक माना गया। इसी के तहत उन्हें देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल एम्स में भर्ती किया गया, जहां हृदय, न्यूरोलॉजी और जनरल मेडिसिन के वरिष्ठ विशेषज्ञ उनकी जांच कर रहे हैं। चिकित्सकों ने प्रारंभिक तौर पर किसी गंभीर या जानलेवा खतरे की आशंका से इनकार किया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी परीक्षण किए जा रहे हैं। एम्स प्रशासन की ओर से बताया गया है कि जगदीप धनखड़ को फिलहाल एक विशेष वार्ड में रखा गया है, जहां उनकी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार, बेहोशी के दौरे कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, हृदय से जुड़ी समस्या, न्यूरोलॉजिकल कारण या दवाओं के दुष्प्रभाव भी शामिल हो सकते हैं। इन्हीं सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ब्रेन स्कैन और अन्य रक्त जांच की जा रही हैं। जगदीप धनखड़ देश के उन संवैधानिक पदाधिकारियों में रहे हैं, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने वर्ष 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे राज्यसभा के सभापति भी रहे और संसद की कार्यवाही के संचालन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उनके इस्तीफे के समय भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी रहे थे। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा और इस दौरान वे राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर मुखर नजर आए। संवैधानिक मर्यादाओं और संघीय ढांचे को लेकर उनकी टिप्पणियां और फैसले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने। इसके अलावा वे लंबे समय तक वकालत और राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में उनका अनुभव व्यापक माना जाता है। उनके एम्स में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चिंता का माहौल देखा गया। विभिन्न दलों के नेताओं, पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। कई नेताओं ने निजी तौर पर भी एम्स प्रशासन से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। हालांकि परिवार और चिकित्सकों की ओर से अपील की गई है कि अफवाहों से बचा जाए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा किया जाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का तीन दिवसीय गुजरात दौरा संपन्न

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से भावपूर्ण विदाई दी गई

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को अपने गुजरात के तीन दिवसीय दौरे को पूर्ण कर अहमदाबाद एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए।

एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी एवं एवं महानुभावों ने भावपूर्ण विदाई दी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, राजनीतिक अग्रणी श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक श्री के. एल. एन. राव, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त श्री जी. एस. मलिक, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी, अहमदाबाद जिला कलेक्टर श्री सुजीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पदाधिकारी ने भावपूर्ण विदाई दी।

सोना-चांदी वायदा ऑल टाइम हाईः सोना वायदा में 2691 रुपये और चांदी वायदा में 11728 रुपये का ऊछाल

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 208438.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 47121.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 161308.22 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 37319 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2890.18 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 39008.26 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 139600 रुपये के भाव पर खूलकर, 141643 रुपये के दिन के उच्च और 139600 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 138819 रुपये के पिछले बंद के सामने 2691 रुपये या 1.94 फीसदी की मजबूती के साथ 141510 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 1370 रुपये या 1.21 फीसदी की तेजी के संग 114326 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 183 रुपये या 1.3 फीसदी की तेजी के संग 14296 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 139279 रुपये के भाव पर खूलकर, 141899 रुपये के दिन के उच्च और 139279 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2513 रुपये या 1.81 फीसदी की तेजी के संग 141210 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 139499 रुपये के भाव पर खूलकर, 141874 रुपये के दिन के उच्च और 139499 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 139030 रुपये के पिछले बंद के सामने 2742 रुपये या 1.97 फीसदी की तेजी के संग 141772 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 262834 रुपये के भाव पर खूलकर, 265481 रुपये के दिन के उच्च और 260711 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252725 रुपये के पिछले बंद के सामने 11728 रुपये या 4.64 फीसदी की मजबूती के साथ 264453 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 11479 रुपये या 4.5 फीसदी की तेजी के संग 266372 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 11471 रुपये या 4.5 फीसदी बढ़कर 266391 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ क्रूड ऑयल वायदा 68 रुपये फिसला : कमोडिटी वायदाओं में 47121.78 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 161308.22 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 39008.26 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37319 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 5283.57 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 36.6 रुपये या 2.86 फीसदी बढ़कर 1317.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 4.25 रुपये या 1.38 फीसदी की तेजी के संग 313.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 10 पैसे या 0.03 फीसदी की नरमी के साथ 317.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 1.55 रुपये या 0.81 फीसदी की तेजी के संग 193.2 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2825.70 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5364 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5364 रुपये और नीचे में 5282 रुपये पर पहुंचकर, 68 रुपये या 1.27 फीसदी घटकर 5284 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 67 रुपये या 1.25 फीसदी लुढ़ककर 5285 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 293.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 297.2 रुपये के दिन के उच्च और 289.3 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 294.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 20 पैसे या 0.07 फीसदी की नरमी के साथ 294 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 30 पैसे या 0.1 फीसदी टूटकर 294.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 989 रुपये पर खूलकर, 7.6 रुपये या 0.77 फीसदी औंधकर 982 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 19327.08 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 19681.18 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4183.04 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 644.07 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 46.49 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 396.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 753.39 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2060.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19822 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 75530 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24708 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 366628 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 37972 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 15176 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 37867 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 98306 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22339 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 51466 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 36812 पॉइंट पर खूलकर, 37349 के उच्च और 36812 के नीचले स्तर को छूकर, 861 पॉइंट बढ़कर 37319 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 59.4 रुपये की गिरावट के साथ 70 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू बिना बदलाव के 14.45 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 763 रुपये की बढ़त के साथ 1505 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5742.5 रुपये की बढ़त के साथ 15569 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1370 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 11.03 रुपये की बढ़त के साथ 22.03 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 65 पैसे के सुधार के साथ 3.59 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 14.2 रुपये की बढ़त के साथ 92.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 20 पैसे की नरमी के साथ 14.5 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 135000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 321 रुपये की गिरावट के साथ 591 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3904 रुपये की गिरावट के साथ 7188.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 17.59 रुपये की गिरावट के साथ 31.35 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.13 रुपये की गिरावट के साथ 1.65 रुपये हुआ।

कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपर्युक्त कार्य के संबंध में 13/14 जनवरी, 2026 की रात को कांदिवली एवं मालाड स्टेशनों के बीच प्वाइंट 103 के डिस्मैंटलिंग हेतु एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त, 14/15 जनवरी, 2026 को कांदिवली एवं मालाड स्टेशनों के बीच प्वाइंट 102 के डिस्मैंटलिंग हेतु भी एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइनों पर 00:00 बजे से 05:30 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक रहेगा।

उपर्युक्त ब्लॉक, पाँचवीं लाइन के निलंबन तथा लगाए गए गति प्रतिबंध के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि अप फास्ट लाइन की कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

1. 13 एवं 14 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।
2. 13 एवं 14 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:

1. 14 एवं 15 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली–नंदुरबार एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।
2. 14 एवं 15 जनवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली उपनगरीय ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

गांधीनगर कैपिटल–वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन

रेल प्रशासन द्वारा गाड़ी संख्या 22468/22467 गांधीनगर कैपिटल–वाराणसी साप्ताहिक एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 05.03.2026 से (जीएनएस)। गांधीनगर कैपिटल–वाराणसी एक्सप्रेस वाराणसी (BSB) स्टेशन के स्थान पर बनारस (BNRS) स्टेशन जाएगी। परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार हैः

गाड़ी संख्या 22468 गांधीनगर कैपिटल–बनारस एक्सप्रेस दिनांक 05.03.2026 से बनारस (BNRS) स्टेशन पर 23.30 बजे पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 22467 बनारस–गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस दिनांक 04.03.2026 से बनारस (BNRS) स्टेशन से 15.10 बजे प्रारंभ होगी।

टर्मिनल परिवर्तन के कारण बनारस स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है। गांधीनगर कैपिटल और लोहता स्टेशनों के बीच समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

इस ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

ज्ञानवापी वजूखाना विवाद पर फिलहाल विराम, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की लंबित सुनवाई को देखते हुए टाली कार्यवाही

(जीएनएस)। प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना का वैज्ञानिक सर्वे कराने से जुड़े संवेदनशील मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय देने से परहेज किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि इस पूरे प्रकरण से संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित है, इसलिए उच्च न्यायालय में इस स्तर पर आगे की कार्यवाही उचित नहीं होगी। इसी आधार पर न्यायालय ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख तीन फरवरी निर्धारित कर दी है।

यह मामला एक बार फिर से उस बहुचर्चित ज्ञानवापी विवाद को चर्चा के केंद्र में ले आया है, जिसने बीते कुछ वर्षों में न केवल न्यायिक हलकों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरी बहस को जन्म दिया है। वजूखाना सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता राखी सिंह की ओर से यह दलील दी गई कि विवादित स्थल की वास्तविक धार्मिक प्रकृति स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे आवश्यक है, ताकि ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया कि वजूखाना परिसर में पहले किए गए निरीक्षण और वीडियोग्राफी के दौरान कुछ ऐसे संकेत सामने आए थे, जिनके आधार पर विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वे कराना जरूरी हो जाता है। याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क है कि आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की मदद से किए गए सर्वे से भ्रम और विवाद की स्थिति को स्थायी रूप से सुलझाया जा सकता है। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना होता है और वैज्ञानिक सर्वे उसी दिशा में एक कदम हो सकता है।

वहीं दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का लगातार विरोध किया है। उनका कहना है कि वजूखाना मस्जिद का अभिन्न हिस्सा है और वहां किसी भी प्रकार का सर्वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में यह भी तर्क रखा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इस पूरे मामले से जुड़े अहम पहलुओं पर विचार कर रहा है, ऐसे में समानांतर रूप से उच्च न्यायालय में सुनवाई से न्यायिक अनुशासन प्रभावित हो सकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित याचिकाएं और अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। अदालत ने यह माना कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के रहते किसी भी प्रकार का आदेश देना उचित नहीं होगा, जिससे भविष्य में न्यायिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। इसी कारण अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया।

इस आदेश के बाद एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी विवाद की दिशा और दशा काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निर्भर करेगी। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने इस प्रकरण में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और निचली अदालतों तथा उच्च न्यायालयों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक मर्यादा और संस्थागत संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पिछले कुछ वर्षों में लगातार कानूनी मोर्चे पर आगे बढ़ता रहा है। वाराणसी की सिविल कोर्ट से शुरू होकर यह मामला उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हर सुनवाई के साथ यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील होता गया है, क्योंकि इसमें आस्था, इतिहास और कानून—तीनों का जटिल संगम देखने को मिलता है।

वजूखाना को लेकर विवाद तब और गहरा गया था जब सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के दौरान कुछ संरचनाओं को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए थे। इसके बाद से ही वैज्ञानिक सर्वे की मांग तेज होती चली गई। हालांकि, अदालतें लगातार यह संकेत देती रही हैं कि किसी भी निर्णय में कानून और सामाजिक सौहार्द—दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई स्थगित किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें तीन फरवरी पर टिकी हैं, जब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। साथ ही यह भी तय माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्यवाही इस विवाद की आगे की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। फिलहाल, अदालत के इस फैसले को एक अस्थायी विराम के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी अंतिम निष्कर्ष के तौर पर।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी।

आंशिक निरस्त होने वाली ट्रेनें:

13 एवं 14 जनवरी, 2026 की ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इस प्रकार यह ट्रेन वसई रोड-बोरीवली के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। 14 एवं 15 जनवरी, 2026 की ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली–अहमदाबाद एक्सप्रेस वसई रोड से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इस प्रकार यह ट्रेन बोरीवली-वसई रोड के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

13 जनवरी की साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस पोकरण स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी

(जीएनएस)। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मण्डल में राईका बाग पैलेस-जैसलमर सेक्शन में जेठा चांदन-थईरात हमीरा स्टेशनों के बीच ब्रिज नं.170 पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु ट्राफिक ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस आंशिक निरस्त रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

13 जनवरी 2026 की ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमर एक्सप्रेस पोकरण स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए यह ट्रेन पोकरण और जैसलमर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। 14 जनवरी 2026 की ट्रेन संख्या 20491 जैसलमर-साबरमती एक्सप्रेस पोकरण स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसलिए यह ट्रेन जैसलमर और पोकरण के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।